

प्रेस सूचना ब्यूरो

भारत सरकार

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में भारत
वंदना पार्क का उद्घाटन किया

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि
नेहरू-लियाकत समझौते का पालन पूर्व में नहीं किया गया किंतु श्री नरेंद्र
मोदी ने इस समझौते का पालन किया और लाखों लोगों को शरण देने का काम
किया है

आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों को सीएए (सिटिजन एमेंडमेंट एक्ट) पढ़ना
चाहिए - श्री अमित शाह

आपको जो राजनीतिक विरोध करना है करो, नरेंद्र मोदी सरकार इस बात
के लिए ठुढ़ है कि आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी - केंद्रीय गृह
मंत्री

सीएए पर विपक्ष देश को गुमराह करने में लगा है - श्री अमित शाह

पूरे देश की जनता द्वारा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री
आवास योजना और आयुष्मान भारत का लाभ लिया जा रहा है किंतु दिल्ली की
जनता इस लाभ को नहीं ले पा रही है - केंद्रीय गृह मंत्री

सीएए नागरिकता लेने का नहीं देने का प्रावधान है - केंद्रीय गृह मंत्री

नई दिल्ली, 17 दिसंबर 2019

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली के द्वारका में भारत वंदना पार्क का
उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत वंदना पार्क आने वाले समय में पर्यटन का सेंटर बनेगा और
दिल्ली आने का मार्ग द्वारिका के इस पार्क से होते हुए पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा।
उनका कहना था कि इस पार्क में भारत के समग्र सांस्कृतिक मानचित्र को उपलब्ध कराया
गया है।



केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि सीएए नागरिकता लेने का नहीं देने का प्रावधान है। उनका कहना था कि नेहरू-लियाकत समझौते का पालन पूर्व में नहीं किया गया किंतु नरेंद्र मोदी ने इस समझौते का पालन किया और लाखों लोगों को शरण देने का काम किया है। श्री अमित शाह ने कहा कि आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों को यह बिल पढ़ना चाहिए, इसमें कहीं पर भी भारत के अल्पसंख्यकों की नागरिकता की बात नहीं की गई है, इसमें केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना सहकर आए वहां के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। श्री शाह का यह भी कहना था कि सीएए पर विपक्ष देश को गुमराह करने में लगा है। उन्होंने विरोध करने वाले राजनीतिक दलों से कहा कि आपको जो राजनीतिक विरोध करना है करो, नरेंद्र मोदी सरकार इस बात के लिए तैयार है कि आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता जाएगी।



श्री शाह ने अनधिकृत कॉलोनी के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार की तरह दिल्ली सरकार भी संकल्प ले लेती तो यह मुद्दा बहुत पहले ही हल हो जाता। उनका कहना था कि श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए संसद में बिल पास कराकर कानून बनाया। उन्होंने अनधिकृत कालोनी के निवासियों से जल्द से जल्द ई-रजिस्ट्री कराने को कहा। श्री अमित शाह ने यह भी कहा कि पूरे देश की जनता द्वारा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत का लाभ लिया जा रहा है किंतु दिल्ली की जनता इस लाभ को नहीं ले पा रही है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पांच लाख तक का खर्चा केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है और सभी तरह के बीमारियों के इलाज के लिए यह राशि प्रदान की जाती है। श्री अमित शाह ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के विकास के लिए हजारों करोड़ रूपए के कार्य किए हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा अब शुरू की जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जनता को पता है कि चुनाव के वक्त जो योजनाएं शुरू की जाती हैं वह कभी पूरी नहीं होती।

एसएनसी/डा.डीडी